



**EPCH**  
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्  
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्  
**EXPORT PROMOTION  
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070  
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253  
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

## प्रेस विज्ञप्ति

# ईपीसीएच ने भारत के हस्तशिल्प सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ के खतरे के मद्देनज़र सरकार से त्वरित कार्रवाई की अपील की

## परिषद ने लक्षित राहत उपायों का प्रस्ताव रखा:

- अमेरिका को किए जाने वाले हस्तशिल्प निर्यात के लिए कॉस्ट इक्वलाइजेशन इंसेंटिव
- इंटरैस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को जारी रखना
- निर्यात पर आयकर छूट

**दिल्ली/एनसीआर, 12 अगस्त 2025** – हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) ने अमेरिका द्वारा भारतीय हस्तशिल्प निर्यात पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद त्वरित कार्रवाई की अपील की है। यह निर्णय न केवल इस क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालता है, बल्कि लाखों कारीगरों की आजीविका पर भी संकट खड़ा कर रहा है। परिषद ने सरकार से आग्रह किया है कि वह निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने और भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन और राजनयिक प्रयासों को तेज करे।

इस संकट पर विचार व्यक्त करते हुए, ईपीसीएच के अध्यक्ष डॉ. नीरज खन्ना ने कहा, “अमेरिका भारत के हस्तशिल्प के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बाजार बना हुआ है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.57 बिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात के साथ अमरीकी बाजार भारत के कुल हस्तशिल्प निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत है। भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों पर 50 प्रतिशत रेसीप्रोकल टैरिफ लगाए जाने और इसके आगे बढ़ने की संभावना की वजह से इस क्षेत्र की व्यवहारिकता पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। टैरिफ का लगा ये झटका अमेरिका को होने वाले निर्यात में 25-30 प्रतिशत की गिरावट ला सकता है, जिससे 400-450 मिलियन अमरीकी डॉलर का संभावित राजस्व नुकसान हो सकता है।”

इस संकट के रणनीतिक समाधान पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. खन्ना ने आगे कहा कि “इन जोखिमों को कम करने के लिए, ईपीसीएच ने कुछ त्वरित राहत उपाय प्रस्तावित रखे हैं, जो स्पष्ट रूप से ‘हस्तशिल्प/हस्त निर्मित’ के रूप में प्रमाणित शिपमेंट पर लागू होंगे। इनमें अमेरिका को होने वाले हस्तशिल्प निर्यात पर दो वर्षों के लिए या जब तक टैरिफ पुनः वार्ता में न आए, 30 प्रतिशत कॉस्ट इक्वलाइजेशन इंसेंटिव (लागत समानता प्रोत्साहन); इंटरैस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम (ब्याज समानता योजना) के लाभों को जारी रखने, जिसमें निर्माता और व्यापारी निर्यातकों दोनों के लिए लाभ 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए; और आयकर अधिनियम की पूर्ववर्ती धारा 80HHC के अनुरूप निर्यात पर आयकर छूट प्रदान की जाए।”

निर्यातक समुदाय की तत्काल चिंताओं को उजागर करते हुए, ईपीसीएच के महानिदेशक की भूमिका में मुख्य संरक्षक और आईईएमएल के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार, ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि “स्थिति तेज और लक्षित कार्रवाई की

मांग करती है। हमारे प्रस्ताव तत्काल लागत असमानताओं को संतुलित करने, खरीदार संबंधों को बनाए रखने और कारीगरों की आजीविका की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। साथ ही, हम अमेरिका के साथ सक्रिय राजनयिक संवाद की मांग कर रहे हैं ताकि भारतीय हस्तशिल्प को उनकी सांस्कृतिक, श्रम-प्रधान और सतत् मूल्य के आधार पर विशेष दर्जा मिल सके। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इस क्षेत्र के भविष्य की रक्षा के लिए वित्तीय और राजनयिक दोनों स्तरों पर शीघ्र कार्रवाई करे।”

इस मौके पर ईपीसीएच के मुख्य संयोजक श्री अवधेश अग्रवाल, ने कहा कि “हमारे निर्यातक हाल के वर्षों के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं, जहां मूल्य निर्धारण, मार्जिन और बाजार स्थिरता को लेकर उन पर लगातार दबाव बना हुआ है। अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से ऑर्डर की कमी या हानि होना खरीदार के विश्वास में कमी और कार्यशील पूंजी की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे व्यापार उन देशों की ओर स्थानांतरित हो सकता है जिन्हें अधिक अनुकूल टैरिफ शर्तें प्राप्त हैं। यदि सरकार समय पर और निर्णायक हस्तक्षेप करती है, तो हम इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं, अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत कर सकते हैं और भारत के हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर पुनः पहचान दिला सकते हैं।”

ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए कहा, “हम सरकार के साथ मिलकर राहत उपायों, जैसे कि आपातकालीन राहत कोष, अमेरिका को भेजे जाने वाले माल के लिए सब्सिडी युक्त माल भाड़ा सहायता, ड्यूटी ड्रॉबैक और आरओडीटीईपी की दरों में वृद्धि, निर्यात प्रोत्साहन मिशन योजना के तहत लक्षित प्रचार योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन, निर्यातकों के लिए दीर्घकालिक ऋण चुकौती पर दो वर्ष की मोहलत, अमेरिका के साथ टैरिफ पर द्विपक्षीय संवाद को तेज करना, साथ ही बाज़ार विविधीकरण, उत्पाद नवाचार और दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना आदि को लागू करने पर कार्य कर रहे हैं।”

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) दुनिया भर के विभिन्न देशों में भारतीय हस्तशिल्प निर्यात को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प उत्पादों और सेवाओं के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि और होम, लाइफस्टाइल, टेक्स्टाइल, फर्नीचर और फैशन जूलरी ऐंड एक्सेसरीज प्रॉडक्ट के उत्पादन में लगे क्राफ्ट क्लस्टर के लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के प्रतिभाशाली हाथों के जादू की ब्रांड इमेज बनाने के लिए जिम्मेदार एक नोडल संस्थान है। इस अवसर पर ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री आर के वर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हस्तशिल्प का कुल निर्यात 33,123 करोड़ रुपये (3,918 मिलियन डॉलर) रहा। इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के दौरान अमरीका को होने वाला हस्तशिल्प का कुल निर्यात 12,814 करोड़ रुपए था (1518.18 मिलियन डालर) रहा।

---

**अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:**

श्री आर. के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक ईपीसीएच;

+91-9810697868



**EPCH**  
हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्  
Export Promotion Council for Handicrafts

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्  
**EXPORT PROMOTION  
COUNCIL FOR HANDICRAFTS**

EPCH HOUSE Pocket 6 & 7 Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070  
Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com | www.epch.in

CIN U20299DL1955NPLO23253  
GST NO: 07AAACE1747M1ZJ

## **PRESS RELEASE**

### **EPCH Urges Urgent Government Action as U.S. Tariff Threatens India's Handicrafts Sector**

#### **Council Proposes Targeted Relief Measures:**

- Cost Equalization for Handicraft Exports to the USA
- Continuation of Interest Equalization Scheme
- Income Tax Exemptions on exports

**Delhi/NCR, 12<sup>th</sup> August 2025** – The Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH) issues an urgent call for action following the United States' imposition of a 50% tariff on Indian handicraft exports, a development that threatens the stability of the sector and the livelihoods of millions of artisans. The Council is urging government for targeted fiscal support, promotional incentives and accelerated diplomatic engagement to help exporters remain competitive and to protect the cultural heritage sustained by India's artisan community.

Speaking on the crisis, Dr. Neeraj Khanna, Chairman – EPCH, said “the United States continues to be India's largest and most significant market for handicrafts, accounting for USD 1.57 billion in exports in FY 2024–25, approximately 40% of India's total handicrafts exports. The recent imposition of a 50% reciprocal tariff on Indian handicraft products, with the possibility of further increases, poses a serious threat to the viability of the sector. This tariff shock could lead to a decline of 25–30% in U.S.-bound exports, translating into a potential revenue loss of USD 400–450 million.

Underlining the strategic way forward Dr. Khanna added further that “to mitigate these risks, EPCH has proposed a set of urgent relief measures, applicable exclusively to shipments clearly documented as ‘Handicraft/Hand Crafted’. These include a 30% Cost Equalisation Incentive for U.S.-bound handicraft exports for two years or until tariffs are renegotiated; continuation of Interest Equalisation Scheme benefits with increased benefits from 3% to 6% for both manufacturer and merchant exporters and Income Tax exemptions be provided in line with erstwhile Section 80HHC of the Income Tax Act.

Highlighting the exporter community's immediate concerns, Dr. Rakesh Kumar, Director General in the role of Chief Mentor, EPCH, and Chairman – IEML shared that “the situation demands urgent and targeted action. Our recommendations are designed to offset the immediate cost disadvantages, sustain buyer relationships and protect artisan livelihoods. At the same time, we are pressing for proactive engagement with the U.S. to secure preferential treatment for Indian handicrafts, given their cultural, labour-intensive, and

sustainable value and we urge the government to act swiftly with both fiscal and diplomatic interventions to safeguard this sector's future.”

Shri Avdesh Agarwal, Chief Convener, EPCH said that “Our exporters are navigating one of the most challenging phases in recent years, facing sustained pressures on pricing, margins and market stability. The U.S. tariff hike brings added risks of order losses, reduced buyer confidence and working capital constraints, with the possibility of trade shifting to countries enjoying more favourable tariff terms. With timely and decisive government intervention, we can transform this challenge into an opportunity, strengthening our competitiveness and achieving renewed global recognition for India's handicrafts.

Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH shared that “We are working with the government to implement relief measures such as an Emergency Relief Fund, subsidised freight support for U.S.-bound consignments, enhanced Duty Drawback and RoDTEP rates, the implementation of targeted promotional schemes under the Export Promotion Mission Scheme at the earliest, a two-year moratorium on long-term loan repayments for exporters, accelerated bilateral engagement with the U.S. for tariff while simultaneously driving market diversification, product innovation, and long-term competitiveness”.

Export Promotion Council for Handicrafts is a nodal agency for promotion of exports of handicrafts from the Country and create brand image of magic of the gifted hands of millions of craftspersons engaged in production of home, lifestyle, textiles, furniture and fashion jewellery & accessories products in different craft clusters of the Country. The overall Handicrafts exports during the year 2024-25 was Rs. 33,123 Crores (US \$ 3,918 Million) and the Handicrafts exports to USA during the year 2024-25 was 12,814.73 crores (US\$ 1,518.18 million) informed by Shri R. K. Verma, Executive Director, EPCH.

---

**For more information please contact:**

Shri. R. K. Verma, Executive Director, EPCH  
+91-9810679868

Encl: Hindi, English version